सीआइटीयू कार्य समिति की भोपाल बैठक का आह्वानः

साम्राज्यवादी हथकण्डों तथा नव–उदार आर्थिक नीतियों के खिलाफ संयुक्त संघर्षो को नयी बुलंदियों पर ले जाओ

□ तपन सेन

गत 28 से 30 दिसंबर तक भोपाल में संपन्न हुयी सीआइटीयू वर्किंग कमेटी की बैठक ने मजदूर वर्ग के आंदोलन का आह्वान किया है कि वह नवउदारवादी आर्थिक नीतियों के हमले के खिलाफ संयुक्त प्रतिरोध को 29 सितंबर की जबर्दस्त देशव्यापी हड़ताल की निरंतरता में नयी बुलंदियों तक ले जाए और इस दिशा में राजनीतिक तथा आर्थिक दोनों ही मोर्चों पर साम्राज्यवादी साजिशों के खिलाफ जनता की व्यापकतम लामबंदी सुनिश्चित करे।

सीआइटीयू अध्यक्ष एम के पंधे द्वारा झंडा फहराए जाने और पदाधिकारियों तथा वर्किंग कमेटी सदस्यों द्वारा शहीद वेदी पर पुष्पांजलि अर्पित किए जाने के साथ मीटिंग शुरू हुयी। सीआइटीयू के मध्यप्रदेश राज्य अध्यक्ष प्रमोद प्रधान ने मीटिंग में स्वागत भाषण दिया।

अध्यक्षीय भाषण

एम के पंधे ने अपने अध्यक्षीय भाषण में विस्तार से अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के घटनाविकासों पर प्रकाश डाला। उनका कहना था कि विश्व जनमत में ज्यादा से ज्यादा अलग–थलग पड़ते जाने के बावजूद अमरीकी साम्राज्यवाद आक्रामकता के साथ अपनी प्रभुत्ववादी साजिश को आगे बढ़ा रहा है।

इराक पर उसका गैरकानूनी कब्जा और इराकी जनता पर उसके अमानवीय अत्याचार जारी हैं। सीरिया, लेबनान और उत्तरी कोरिया के खिलाफ उसके आक्रामक तेवर बने हुए हैं। क्यूबा के खिलाफ उसकी नाकेबंदी निरंतर जारी है। पश्चिमी तट में फिलीस्तीनी क्षेत्र पर अपना कब्जा बनाए रखने के लिए इजराइल को उसका प्रोत्साहन जारी है। ये सब इस बात के गवाह हैं कि उसकी आक्रामकता बनी हुयी है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को कमतर बनाने की अमरीका की ऐसी साजिश और अमरीकी साम्राज्यवाद के निशाने पर आए देशों की राष्ट्रीय संप्रभुता के खिलाफ उसकी ऐसी आक्रामक साजिश के खिलाफ विरोध की आवाज खुद अमरीका के भीतर ही ज्यादा से ज्यादा बुलंद होती जा रही है।

इराक के भीतर अमरीकी कब्जे का विरोध बढ़ रहा है। इसके चलते हर रोज अमरीकी सैनिक हताहत हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने गत 8 नवंबर को जो प्रस्ताव स्वीकार किया है उसमें अमरीका सरकार का यह आह्वान किया गया है कि वह क्यूबा के खिलाफ आर्थिक नाकेबंदी खत्म करे।

इस प्रस्ताव को महासभा में जबर्दस्त समर्थन मिला था और 191 में से 182 देश उसके पक्ष में थे। पंधे ने कहा कि इससे पता चलता है कि विश्व राजनीति में अमरीकी साम्राज्यवाद ज्यादा से ज्यादा अलग–थलग पड़ता जा रहा है।

आर्थिक मोर्चे पर घटनाविकास भी यही दिखाता है कि साम्राज्यवादी शक्तियों की प्रभुत्ववादी साजिश आक्रामक ढ़ंग से जारी है,जो अपनी राजनीतिक तथा सैन्य रणनीति के अनुरूप विकासशील देशों का आर्थिक उपनिवेशीकरण करना चाहती हैं।

बढ़ती गरीबी और रोजगारहीनता

साथ ही साथ इससे यह भी बखूबी पता चलता है कि नवउदारवादी आर्थिक उदारीकरण का वह बहुप्रचारित मॉडल, जिसमें दुनिया भर की जनता के लिए समृद्धि का वादा किया गया था, बुरी तरह विफल रहा है।

गरीबी और बढ़ी है और गरीबी की रेखा के नीचे रहनेवाले लोगों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। बेरोजगारी और अर्द्धबेरोजगारी आम फिनोमिना बन गया है और विकसित देश जो नीतियां अपना रहे हैं और जिन्हें विश्व बैंक, आइ एम एफ तथा डब्ल्यू टी ओ के जरिए विकासशील देशों पर थोपा जा रहा है,उन्होंने रोजगारहीनता तथा गरीबी की स्थिति को हर गुजरनेवाले दिन के साथ और बदतर बनाया है।

पंधे का कहना था कि डब्ल्यू टी ओ की हाल ही में हांगकांग में संपन्न हुयी मंत्रीस्तरीय बैठक के परिणाम उन अन्यायपूर्ण शर्तों के गवाह हैं, जो विकासशील देशों पर थोपी जा रही हैं।

लेकिन अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में आज की सबसे उल्लेखनीय खासियत है मजदूरों और जनता पर नवउदारवादी आर्थिक नीतियों के भयंकर असर के खिलाफ मजदूर वर्ग के बढ़ते संघर्ष। पिछले वर्ष 29 सितंबर को भारत में हुयी देशव्यापी आम हड़ताल ऐसे ही उदारीकरणविरोधी विश्वव्यापी संघर्षों के बीच आयोजित की गयी थी।

नव उदारवादी नीतियों के प्रभाव के खिलाफ और आम जनता के अधिकारों तथा उनकी रोजी–रोटी पर होनेवाले हमलों के खिलाफ हड़ताल की लहरें सचमुच पूरी दुनिया में फैल चुकी हैं।

पंधे ने कहा कि सुपर मुनाफों तथा जनता के बीच के विश्विक युद्ध में जनता ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है

और वह नवउदारवादी साम्राज्यवादी विश्वीकरण के इस सिद्धांत को चुनौती दे रही है कि विश्वीकरण को टाला नहीं जा सकता।

महासचिव की रिपोर्ट

चित्तब्रत मजूमदार ने महासचिव की रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में यूपीए सरकार की विदेश नीति में आए अमरीकापरस्त झुकाव को दिखाया गया था,जैसा कि ईरान की नाभिकीय नीति के मामले में सामने आया है और जो हमारे राष्ट्रीय हितों के बहुत ही खिलाफ है।

यही बात भारत-अमरीकी संयुक्त सैन्य अभ्यास के मामले में भी सामने आयी है, जो देशभर में इसके खिलाफ आयोजित प्रदर्शनों के बावजूद आयोजित किया गया।

रिपोर्ट में कहा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अधिकतर में इस तरह का कट्टर अमरीकापरस्त रुख, साझा न्यूनतम कार्यक्रम में किए गए वादों का पूरी तरह उल्लंघन है।

साझा न्यूनतम कार्यक्रम में यह कहा गया है कि एक स्वतंत्र विदेश नीति लागू की जाएगी।

साम्राज्यवाद द्वारा चलायी जा रही नवउदारवादी आर्थिक नीति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की पृष्ठभूमि और डब्ल्यू टी ओ की हांगकांग बैठक में भारतीय वार्ताकारों ने जिस तरह से आत्मसमर्पणकारी रुख दिखाया और जिसके चलते समर्पण पूरी तरह बेनकाब हो गया,उसे देखते हुए संप्रग सरकार की विदेश नीति में आया यह साम्राज्यवादपरस्त झुकाव किसी भी तरह असामान्य नहीं दिखायी देता।

महासचिव का यह कहना था कि इसीलिए यह मजदूरवर्ग के आंदोलन का सबसे प्रमुख काम बन गया है कि वह संप्रग सरकार की विदेश नीति में ऐसे अमरीकापरस्त झुकाव के खिलाफ, राजनीतिक तथा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में साम्राज्यवादपरस्त तथा अमरीकापरस्त हर रुख के खिलाफ व्यापकतम लामबंदी के जरिए प्रतिरोध का निर्माण करे, क्योंकि उसके बिना साम्राज्यवादविरोधी आंदोलन को प्रभावी ढ़ंग से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।

संप्रग सरकार की भी वही नीतियां

रिपोर्ट में विस्तार से यह बताया गया था कि कैसे और कितने जोर-शोर से उसी नवउदारवादी आर्थिक नीति को संप्रग सरकार द्वारा लागू किया जा रहा है,जिसने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को भंयकर नुकसान पंहुचाया है और जिसके चलते मुठ्ठीभर पूंजीपति तो भारी मुनाफे बटोर रहे हैं,लेकिन गरीबी गहराती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरह बदहाल है और सैकड़ों की तादाद में लोगों ने खुदकशी की है।

रिपोर्ट में बताया गया था कि ट्रेड यूनियन आंदोलन और वामपंथी पार्टियों के निरंतर दबाव के चलते राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून पास किया गया है और संप्रग सरकार के तहत आर्थिक नीति के मोर्चे पर यही एक धनात्मक कानूनी कार्रवाई हुयी है।

रिपोर्ट में यह बताया गया था कि संपूर्ण ट्रेड यूनियन आंदोलन के विरोधों के बावजूद सरकार निजीकरण तथा उदारीकरण की उसी नीति पर चल रही है। यह न्यूनतम साझा कार्यक्रम का उल्लंघन है। हवाई अड्डों का निजीकरण, अर्थव्यवस्था के रणनीतिक तथा संवेदनशील क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ाना, वित्तीय क्षेत्र का उदारीकरण आदि सभी जनता और अर्थव्यवस्था के हितों के खिलाफ हैं।

रिपोर्ट में कहा गया था कि इसके साथ ही साथ हायर एंड फायर की व्यवस्था शुरू करने के लिए और मजदूरों के भारी बहुमत को श्रम कानूनों के दायरे से बाहर करने के लिए श्रम कानूनों में मालिकानपरस्त बदलाव लाने की जोरदार कोशिशें की जा रही हैं।

तथाकथित श्रम बाजार नमनीयता लाने के लिए नीतिगत मुहिम के हिस्से के तौर पर इस बात को प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि श्रम कानूनों को लागू ही न किया जाए और केंद्र सरकार तथा अधिकतर राज्य सरकारें इस तरह की गैरकानूनी गतिविधियों में संलग्न हैं।

न्यूनतम वेतन, काम के घंटों, सामाजिक सुरक्षा लाभों, ठेके के काम, सुरक्षा आदि से संबंधित तमाम बुनियादी श्रम कानूनों को खुद कानून लागू करनेवाली मशीनरी ही पांवों तले कुचल रही है। और अब तो खुद सरकार ही इस तरह की गैरकानूनी गतिविधियों को कानूनी रूप देने के लिए श्रम कानूनों में बदलाव लाने के लिए दिन-रात जुटी है। मजूमदार का कहना था कि यह नवउदारवादी व्यवस्था के तहत पूंजी के हितों के सामने सरकारों के पालतू बन जाने का ही प्रतिबिंबन है।

इसलिए रिपोर्ट में यह कहा गया था कि मजदूर वर्ग के आंदोलन को नवउदारवादी आर्थिक नीति की मुहिम के खिलाफ और साथ ही साथ मजदूर वर्ग के अधिकारों तथा उनकी रोजी-रोटी पर होनेवाले हमलों को मात देने के लिए एक मजबूत प्रतिरोध का निर्माण करना होगा।

29 सितंबर की आम हड़ताल की भारी सफलता नए चरण में इस तरह के संघर्ष की शुरूआत थी और इस संघर्ष को नयी बुलंदियों तक ले जाने की जरूरत है और इस नीतिगत व्यवस्था को पलटने के लिए मजबूर करने के लिए जनता की व्यापक लामबंदी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

और महासचिव का कहना था कि व्यापक जन लामबंदी की प्रक्रिया के जरिए ही मजदूर वर्ग के आंदोलन को देश और जनता की एकता की दुश्मन सांप्रदायिक तथा विभाजनकारी शक्तियों को अलग-थलग करने तथा उन्हें हाशिए पर डालने में सक्षम बनना होगा।

रिपोर्ट पर बहस

महासचिव की रिपोर्ट पर हुयी बहस में 30 कॉमरेडों ने भाग लिया। वक्ताओं ने अपने अनुभव बताते हुए इस जरूरत पर जोर दिया कि उस संघर्ष की निरंतरता को बनाए रखना जरूरी है, जो 29 नवंबर की

आगामी संघर्ष

सीआइटीयू वर्किंग कमेटी ने आनेवाले दिनों में निम्नलिखित कार्रवाइयां आयोजित करने का निर्णय लिया:

29 सितंबर की हड़ताल के बाद कार्रवाइयां:

16 सूत्री मांगों पर बिल्कुल निचले स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। संसद के बजट सत्र के समय इस अभियान को व्यापकतम केंद्रीय लामबंदी के रूप में अपने उत्कर्ष पर पंहुचना चाहिए। सीआइटीयू इस केंद्रीय लामबंदी, जिससे पहले राज्य तथा जिला स्तरीय संयुक्त अभियान चलाए जाएंगे, को अंतिम रूप देने के लिए केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की आयोजन समिति के दूसरे घटकों से विचार-विमर्श करने की पहल करेगी। सीआइटीयू का स्वतंत्र अभियान साथ-साथ जारी रहेगा।

श्रम अधिकारों पर हमलों, श्रम कानूनों को लागू न किए जाने और श्रम कानूनों में मालिकानपरस्त बदलाव लाने के सरकार के कदम के खिलाफ:

25 जनवरी से 31 जनवरी तक विरोध सप्ताह मनाया जाएगा। यह सप्ताहव्यापी अभियान पूरे देश में 31 जनवरी को राज्य तथा जिलास्तरीय जबर्दस्त प्रदर्शनों, धरनों, रैलियों और घेरावों आदि के रूप में अपने उत्कर्ष पर पंहुचेगा।

अगर संसद में कोई मजदूरविरोधी विधेयक लाया जाता है या ऐसे किसी विधेयक के संबंध में सरकार अपने किसी निर्णय की घोषणा करती है तो सीआइटीयू की सभी कमेटियों तथा इकाइयों को अल्पावधि नोटिस पर देशव्यापी विरोध कार्रवाइयों के लिए तैयार रहना चाहिए।

साम्राज्यवादविरोधी प्रदर्शन:

सीआइटीयू को वामपंथी पार्टियों तथा जनतांत्रिक संगठनों के आह्वान पर 24 जनवरी को आयोजित किए जानेवाले साम्राज्यवादविरोधी प्रदर्शनों तथा लामबंदियों में शामिल होना चाहिए।

फरवरी महीने में किसी समय अमरीकी राष्ट्रपति जार्ज बुश भारत यात्रा पर आनेवाला है। उसकी यात्रावाले दिन पूरे देश में जबर्दस्त विरोध प्रदर्शनों का आयोजन किया जाना चाहिए। सीआइटीयू कमेटियों तथा इकाइयों को इसके लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए और बुशविरोधी प्रदर्शनों में एन पी एम ओ को शामिल करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

सीआइटीयू को मई महीने में हैदराबाद में होने जा रही एशियाई विकास बैंक की वार्षिक आम बैठक के पहले ही दिन जोरदार प्रदर्शन का आयोजन करने के लिए पहल करनी चाहिए। हैदराबाद प्रदर्शन में हमें दूसरी ट्रेड यूनियनों को शामिल करने का भी प्रयास करना चाहिए।

सीआइटीयू को निम्नलिखित क्षेत्रवार कार्यक्रमों तथा कार्रवाइयों के साथ जुड़ना चाहिए और एकजुटता व्यक्त करनी चाहिए:

टेलीकॉम क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाए जाने तथा बी एस एन एल के केबल नेटवर्क का निजी टेलीकॉम प्लेयरों को इस्तेमाल करने की छूट देने के खिलाफ और अन्य नीतिगत मुद्दों को लेकर 5 जनवरी को होने जा रही बी एस एन एल कर्मचारियों तथा अधिकारियों की देशव्यापी हड़ताल के साथ सीआइटीयू को जुड़ना चाहिए और एकजुटता व्यक्त करनी चाहिए। 5 जनवरी की इस हड़ताल का आह्वान सभी कर्मचारी यूनियनों तथा आफिसर्स एसोसियशनों ने किया है।

एक समुचित राष्ट्रीय सड़क परिवहन नीति की मांग करते हुए और विभिन्न राज्य परिवहन निगमों के निजीकरण के खिलाफ और अन्य मांगों को लेकर अखिल भारतीय सड़क परिवहन वर्कर्स फेडरेशन के आह्वान पर आगामी 7 मार्च को होनेवाले संसद मार्च से जुड़ना चाहिए तथा एकजुटता व्यक्त करनी चाहिए।

वर्किंग कमेटी की मीटिंग के अंतिम दिन 30 दिसंबर को दोपहर बाद भोपाल में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसे पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री मोहम्मद अमीन, सीआइटीयू के अध्यक्ष तथा महासचिव क्रमश: एम के पंधे तथा चित्तब्रत मजूमदार, सीआइटीयू सचिवगण सांसद दीपांकर मुखर्जी तथा के हेमलता और मध्यप्रदेश राज्य सीआइटीयू के महासचिव बादल सरोज ने रैली को संबोधित किया। मध्यप्रदेश राज्य सीआइटीयू के अध्यक्ष प्रमोद प्रधान ने रैली की अध्यक्षता की।

आम हड़ताल के जरिए उन्मुक्त हुआ है और आनेवाले दिनों में खासतौर से ट्रेड यूनियन अधिकारों तथा श्रम कानूनों शासक राजनीति के नियोजित हमलों और उदारीकरण की उसी नीति को आक्रामक ढ़ंग से लागू करने के मद्देजनर जिसके लिए चरणबद्ध कार्यक्रम, संयुक्त अभियान, आंदोलन और कार्रवाइयां आयोजित की जाएंगी।

वर्किंग कमेटी ने ''ट्रेड यूनियन आंदोलन में कैडर का विकास'' विषय पर विशेष बहस का आयोजन किया था।

सीआइटीयू की पिछली जनरल कांउसिल मीटिंग, जो पिछले वर्ष जुलाई में हुयी थी, में हुए विचार-विमर्श के आधार पर चर्चा पत्र को फिर से तैयार किया गया था,जिसे सीटू सचिव कनाई बनर्जी ने पेश किया।

इस विषय पर हुए विचार-विमर्श में 14 सदस्यों ने भाग लिया और चर्चा पत्र द्वारा रेखांकित किए गए विषय पर समझ को समृद्ध बनाने के लिए मूल्यवान सुझाव दिए।

बहस के बाद यह निर्णय लिया गया कि सीआइटीयू सेक्रेटेरियट वर्किंग कमेटी के कॉमरेडों द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर इस दस्तावेज को अंतिम रूप देगा और सभी इकाइयों को सर्कुलेट करेगा।

सीआइटीयू महासचिव चित्तब्रत मजूमदार ने रिपोट पर हुयी बहस में उठे मुद्दों का जवाब दिया, जिसके बाद वर्किंग कमेटी ने सर्वसम्मति से रिपोर्ट स्वीकार कर ली।

वर्किंग कमेटी ने ट्रेड यूनियन कैडर तथा कार्यकर्ताओं के लिए शिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने और ट्रेड यूनियन आंदोलन के लिए प्रासंगिक मुद्दों पर रिसर्च कार्य के लिए एक इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेड यूनियन एंड रिसर्च स्थापित करने का भी निर्णय लिया है।

यह संस्थान सीआइटीयू के संस्थापक महासचिव और भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के दिग्गज पी राममूर्ति के नाम पर स्थापित किया जाएगा। इस संस्थान को स्थापित करने, चलाने और कक्षाओं तथा शोध कार्य का ढ़ांचा तैयार करने में सीआइटीयू ने बिरादराना ट्रेड यूनियन संगठनों का सहयोग लेने का भी निर्णय लिया है।

वर्किंग कमेटी के प्रस्ताव

वर्किंग कमेटी ने दस प्रस्ताव स्वीकार किए। ये प्रस्ताव इस प्रकार हैं: उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के कांच के चूड़ी तथा सिरामिक इंडस्ट्री के मजदूरों के बर्बर दमन के खिलाफ, मुनाफा देनेवाली सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का विनिवेश करने के संप्रग सरकार के कदम के खिलाफ, कार्यस्थलों पर होनेवाली दुर्घटनाओं तथा सुरक्षा प्रावधानों की अनदेखी पर, ई पी एफ की ब्याज दर घटाने के विरोध में और ई पी एफ की ब्याज दर 9.5 फीसद बनाए रखने के लिए ब्याज की दरों में बढ़ोतरी की मांग करते हुए, यूपीए सरकार से पी एफ आर डी ए विधेयक को निरस्त करने की मांग करते हुए, छठे वेतन आयोग की स्थापना करने के लिए दबाव बनाने की खातिर केंद्र सरकार कर्मचारियों तथा रेल कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल के प्रति समर्थन का इजहार करते हुए, टेलीकॉम क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने के खिलाफ 5जनवरी को होनेवाली बी एस एन एल कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल को समर्थन देते हुए, कारखानाबंदी, विक्टीमाइजेशन तथा दमन के खिलाफ लुधियाना के साइकिल मजदूरों को समर्थन देते हुए, लौह अयस्क और अन्य मूल्यवान खनिजों के बड़े पैमाने पर निर्यात को बंद करने की मांग करते हुए और मध्यप्रदेश तथा खासतौर से भोपाल की जनता को और सीआइटीयू की मध्यप्रदेश राज्य कमेटी को सीआइटीयू वर्किंग कमेटी की बैठक सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए बधाई देते हुए पारित प्रस्ताव। □

बाजार का बढ़—फूल रहा है पर श्रमिकों के मूल्य के मूल्य पर...

भारतीय प्रबंधन अधिकारियों के वेतन तेजी से बढ़ रहे हैं; वेतन सम्बन्धी सर्वेक्षणों से पता चलता है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत के कार्यकारी अधिकारियों के वेतन सबसे अधिक हैं। किन्तु यह सब भारत के श्रमिकों के मूल्य पर हो रहा है क्योंकि उत्पादन की कुल लागत में तेजी से गिरावट आ रही है। यह अनुपात वर्ष 2000—01 में 9.54 प्रतिशत था जबकि वर्ष 2004—05 में यह गिर कर 8.13 प्रतिशत रह गया। कुल लागत के 1.41 प्रतिशत की बचत ने 2004—05 में नैगम क्षेत्र को 17,284 करोड़ रुपये का लाभ पहुंचाया था और उसी वर्ष उसके लाभ में 53.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

रुचिकर बात तो यह है कि इस अवधि में परिचालन लाभ में कोई सुधार दिखाई नहीं देता; यह 2000—01 में बिक्री का 24.8 प्रतिशत था और 2004—05 में 24.26 प्रतिशत हो गया। दूसरे शब्दों में, श्रमिकों पर होने वाले 'खर्चे' के अलावा इस अवधि में होने वाली लागत में कोई बचत नहीं हुई थी।

इस अध्ययन में 3338 कम्पनियों का सर्वेक्षण किया गया जिनमें से 3197 निजी क्षेत्र की तथा 141 सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियां हैं। इन्हीं कम्पनियों के बारे में केपिटेलाइन पलस डाटा बेस से पिछले पांच वर्षों के लिये वित्तीय सूचनाएं उपलब्ध हो सकी हैं। श्रम सम्बन्धी लागत में वेतन, पारिश्रमिक तथा बोनस, कर्मचारियों के कल्याण पर होने वाले खर्च, ग्रैच्युटी तथा कर्मचारियों पर होने वाले दूसरे खर्च शामिल हैं किन्तु इन खर्चों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की क्षतिपूर्ति शामिल नहीं है।

मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नये रोजगार का सर्वथा अभाव पाया जा रहा है; यही इसका सबसे अधिक चौंका देने वाला कारण है; दूसरे शब्दों में मैन्युफैक्चरिंग कम्पनियों ने भारत में अपना कारोबार तो बढ़ाया है किन्तु उसके अनुरूप नये रोजगारों का सृजन नहीं किया। निजी क्षेत्र की मैन्युफैक्चरिंग कम्पनियों की उत्पादन लागत में श्रमिकों का भाग वर्ष 2000—01 के 7.52 प्रतिशत से कम हो कर 2004—05 में 6.04 प्रतिशत रह गया है। सार्वजनिक कम्पनियों में भी श्रम सम्बन्धी लागत इसी अवधि में 5.26 प्रतिशत से कम होकर 3.95 प्रतिशत रह गई है। (बिजनस स्टैंडर्ड, 04—01—2006)